www.ijarp.com ISSN 2456-9992 Page: 01-09

International Journal Advanced Research Publications

Research Article

Volume: 02
Issue: 11

वोकल फॉर लोकल अभियान को नीति और शासन का समर्थन

*[1]डॉ. रेखा सूर्यवंशी, [2]डॉ. सरोज विक्रम रत्नाकर

[1]सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान [2]सहायक प्राध्यापक, प्राणीशास्त्र

शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन

Article Received: 08 October 2026, Article Revised: 28 October 2026, Published on: 17 November 2026

***Corresponding Author: डॉ. रेखा सूर्यवंशी**

सहायक प्राध्यापक, गृह विज्ञान शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन

Doi: https://doi-doi.org/101555/ijrpa.9792

सारांश

वोकल फॉर लोकल अभियान भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आरंभ किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों, स्थानीय कारीगरों, MSMEs तथा पारंपरिक हस्तशिल्प को आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। यह शोध पत्र नीति एवं शासन के दृष्टिकोण से इस अभियान के समर्थन का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शोध कार्य का उददेश्य वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए शासन की नीतियो का अध्ययन करना था| अध्ययन में वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए शासन की नीतियों से सम्बंधित तथ्यों को एकत्रित करने हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित नीतियों का अध्ययन किया गया शोध में पाया गया कि ODOP (एक जिला और एक उत्पाद), स्टार्टअप इंडिया , GeM Portal, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (CGTMSE), खादी ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास, खादी और विपणन सहायता योजना पी एमएस, महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए वुमनिया कार्यक्रम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्योग समूह विकास, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड जैसी योजनायें वोकल फॉर लोकल की सफलता में केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। इसके अतिरिक्त, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग की बढ़ती उपयोगिता ने ग्रामीण शिल्प एवं छोटे उद्यमों के लिए नए अवसर खोले हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यदि वोकल फॉर लोकल अभियान को नीति और शासन दोनों स्तरों पर निरंतर सहयोग मिलता रहे तो वोकल फॉर लोकल अभियान न केवल रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय नवाचारों को भी वैश्विक पहचान दिलाने

में सक्षम होगा। यह अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम साबित हो सकता है।

मुख्य शब्द: वोकल फॉर लोकल, शासन की नीति , आर्थिक आत्मनिर्भरता, कौशल विकास |

प्रस्तावना- वोकल फॉर लोकल का अर्थ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना हैं। इसके अंतर्गत देश को स्वयं वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए और वहां के प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही देश में बनी हुई वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए| जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके| 'वोकल फॉर लोकल' योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में कोविड- 19 महामारी ने जब विश्व अर्थव्यवस्था को हिला दिया, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने "आत्मनिर्भर भारत" का नारा दिया और इसके अंतर्गत "वोकल फॉर लोकल" अभियान की घोषणा की। इस अभियान के द्वारा स्थानीय उत्पादों का उत्पादन, प्रचार और उपभोग बढेगा| साथ ही भारतीय उद्योग आत्मनिर्भर होगे | वोकल फॉर लोकल भारतीय उद्यमियों में गर्व की भावना जगाने का कार्य करता है। वोकल फॉर लोकल केवल भारत को आर्थिक रूप से ही सशक्त नहीं बनाएगा, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति भी है|
सार्वजनिक खरीद किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसका सीधा असर उस देश के नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। जब सरकार वस्तुओं और सेवाओं की कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से खरीदारी करती हैं, तो इससे न केवल सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होता है, बल्कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग आदि के व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसर भी बढ़ते हैं। इससे रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा और समग्र सामाजिक विकास में योगदान मिलता है ।

वोकल फॉर लोकल अभियान का महत्व- वोकल फॉर लोकल अभियान घरेलू उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाकर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। वोकल फॉर लोकल अभियान से स्थानीय निर्माण और उत्पादन को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे बेरोजगारी कम होती है। स्थानीय उत्पादों के उपयोग और प्रचार से विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता कम होती है, जिससे देश का धन देश में ही रहता है। यह नीति व्यवसायों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और नवीनता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वोकल फॉर लोकल अभियान से पारंपरिक शिल्प, हथकरघा और स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है। इसका लक्ष्य ऐसे स्थानीय ब्रांडों का निर्माण करना है जो 'स्थानीय से

वैश्विक' बनें और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत का प्रतिनिधित्व करें। वोकल फॉर लोकल अभियान कुटीर, घरेलू और लघु उद्योगों को पुनर्जीवन प्रदान करके अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मजबूत करता है।

वोकल फॉर लोकल अभियान के उददेश्य- स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर वस्तुओं के उत्पादन, विनिर्माण और आपूर्ति में आत्मनिर्भरता लाना, विदेशी उत्पादों पर देश की निर्भरता को कम करना, छोटे व्यवसायों को समर्थन देकर ई-पोर्टल और अन्य सरकारी पहलों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को स्थानीय उत्पादों और उनके महत्व के बारे में जागरूक करना एवं स्थानीय उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और नवाचार में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना आदि वोकल फॉर लोकल अभियान के उददेश्य है |

अध्ययन का उद्देश्य – 1. वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए शासन की नीतियो का अध्ययन करना

साहित्य की समीक्षा

पीयूष द्विवेदी , डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन **(2021)** "वोकल फॉर लोकल' से खुलेगी आत्मनिर्भरता की राह" के लेख के अनुसार वोकल फॉर लोकल अभियान से देश के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा जिससे छोटे-छोटे उद्यमियों का विकास होगा और धीरे-धीरे उनके उत्पाद वैश्विक बनते जाएंगे| लोगो में वोकल फॉर लोकल अभियान के प्रति धीरे-धीरे जागरूकता आने लगी है और लोग स्थानीय उत्पादों की और आकर्षित होने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने इस आकर्षण को व्यक्त करते हैं।

नीति आयोग की बेस्ट प्रेक्टिसेस का शीर्षक 'भारतीय खिलौना उद्योग को पुनर्जीवित करना प्रधानमंत्री मोदी जी का 'वोकल फॉर लोकल' अभियान और उसका प्रभाव" के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान और **2021** में **टॉयकैथॉन और इंडिया टॉय फेयर** जैसी पहलों के शुभारंभ ने भारतीय खिलौना उद्योग में एक उल्लेखनीय बदलाव की शुरुआत की है। इस अभियान ने स्थानीय स्तर पर निर्मित खिलौनों की मांग को बढ़ावा दिया है, जिससे घरेलू खिलौना उत्पादन में वृद्धि हुई है। इससे आर्थिक स्थिति पर सार्थक प्रभाव पाया गया क्योंकि इसने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए हैं| इसने देश की विदेशी खिलौनों पर निर्भरता को कम किया है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।

नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्यम उद्यमों के लिए एक ऐसी नीति डिजाइन करना था, जिसमें स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और एमएसएमई विकास पर जोर दिया गया था।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष एमएसएमई भारत की जीडीपी में लगभग 29% और निर्यात में 40% का योगदान करते हैं और 60% से अधिक रोजगार देते हैं, पंजीकृत एमएसएमई में से 97% सूक्ष्म उद्यम हैं, जबकि मध्यम उद्यमों की संख्या बहुत कम (0.3%) है। कम संख्या में होने के बावजूद, मध्यम उद्यम एमएसएमई निर्यात में 40% का योगदान देते हैं, जो उनकी नवाचार क्षमता को दर्शाता है।रिपोर्ट में मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे वित्तीय बाधाओं, प्रौद्योगिकी अपनाने की कमी और कौशल की कमी का विवरण है। इन समस्याओं को हल करने के लिए, रिपोर्ट ने नीति डिजाइन, सहकारी शासन, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, और कौशल विकास जैसे उपाय सुझाए हैं।

अभिलाषा साहू (2023) के द्वारा वोकल फोर लोकल की प्रासंगिकता आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में विषय पर शोध कार्य किया गया | जिसका उददेश्य भारत में आत्मनिर्भरता में वोकल फॉर लोकल की आवश्यकता, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल का अध्ययन करना था| अभिलाषा साहू के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का विकास व प्रचार प्रसार हीआत्मनिर्भरता के द्वार की कुंजी है। केन्द्र व राज्य सरकार विभिन्न योजना व कार्यक्रम जैसे-एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम, हुनर हाट, राष्ट्रीय खिलौना मेला, प्रदर्शिनी आदि के द्वारादेश में स्थानीय उत्पाद को बढावा देने के लिए आवश्यकतानुसार प्रयास किया जा रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीआईबी दिल्ली द्वारा 02 मार्च 2025 को भारत की अर्थव्यवस्था पर GeM का रणनीतिक प्रभाव विषय पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई | जिसमे भारत की अर्थव्यवस्था में GeM का वोकल फॉर लोकल में योगदान पर चर्चा की| रिपोर्ट में बताया की सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देकर भारत में सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह बदल दिया है। स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और एमएसएमई को सशक्त बनाकर, GeM आर्थिक विकास और सामाजिक समता को बढ़ावा देता है। इस प्लेटफ़ॉर्म की रणनीतिक पहलों, जैसे SWAYATT, स्टार्टअप रनवे 2.0 और वुमनिया, ने व्यापार को आसान बनाने और सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। GeM के निरंतर विकास के साथ, यह एक स्थायी, खुले और प्रतिस्पर्धी बाज़ार के निर्माण के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है, जो समावेशी और पारदर्शी सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाओं की दिशा में भारत की प्रगति को गति प्रदान करता है। राष्ट्र के सामाजिक विकास के अनुरूप, GeM ने स्टार्टअप्स को ₹35,950 करोड़ मूल्य के ऑर्डर पूरे करने में सक्षम बनाया है। GeM पर कुल विक्रेता आधार में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 8% है, और GeM पोर्टल पर पंजीकृत उद्यम-सत्यापित महिला सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) की संचयी संख्या 1,77,786 है, जिन्होंने कुल ₹46,615 करोड़ मूल्य के ऑर्डर पूरे किए हैं ।

उपरोक्त पूर्व साहित्य की समीक्षा से निष्कर्ष निकलता है कि "सरकारी नीति समर्थन से लोकल उत्पादों की पहचान और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है।

वोकल फॉर लोकल अभियान को नीति और शासन का समर्थन- वोकल फॉर लोकल अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कई योजनाये प्रारंभ की गयी है|

'एक जिला, एक उत्पाद' (ODOP) और वोकल फॉर लोकल अभियान - 'वोकल फॉर लोकल' नीति जमीनी स्तर से जुड़कर कार्य करती है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना, उसका ब्रांड बनाना और उसे बढ़ावा देना है। एक जिला, एक उत्पाद पहल 'वोकल फॉर लोकल' के सिद्धांत से प्रेरित है, जो स्थानीय उत्पादों की मांग को बढ़ाकर घरेलू उद्योगों को सशक्त बनाता है और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करता है। एक जिला, एक उत्पाद जो कि 'वोकल फॉर लोकल' के अंतर्गत है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करता है और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत नए उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए इस योजना को सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया | पीएमईजीपी एक प्रमुख ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना को खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ आयोग (केवीआईसी) द्वारा लागू किया जाता है जो राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। राज्य स्तर पर, इस योजना को राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्डों (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से लागू किया जाता है। इस योजना में नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए विनिर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत ₹50 लाख और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह ₹20 लाख है। इस योजना के लिए 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। लाभार्थी केवल पीएमईजीपी ई-पोर्टल के माध्यम से योजना के अंतर्गत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं|

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (CGTMSE) – सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSE) के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGTMSE) भारत सरकार की एक स्कीम है जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बिना किसी तीसरे व्यक्ति की गारंटी के लोन दिलाने करने में मदद करती है। यह योजना सूक्ष्म और लघु उद्यमों को क्रेडिट (लोन) की उपलब्धता में सुधार करने और उनके

विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। यह योजना का उददेश्य वित्तीय संस्थानों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, ताकि वे बिना किसी संपार्श्विक के ऋण दे सकें। यह योजना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जोखिम से बचाती है, जिससे वे अधिक ऋण देने को प्रोत्साहित होते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण के लिए सीधे संबंधित बैंकों या वित्तीय संस्थानों से संपर्क करना होता है।

खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों का विकास- खादी, ग्राम और कॉयर उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (KVGY) और ग्रामोद्योग विकास योजना (GVY) जिनमें कारीगरों को कौशल विकास, मशीनरी और टूल किट जैसी सहायता दी जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

खरीद और विपणन सहायता योजना (पी. एम. एस.) - खरीद और विपणन सहायता योजना (पी. एम. एस.) विपणन संवर्धन योजनाएं से सम्बंधित है | खरीद और विपणन सहायता योजना (पी. एम. एस.) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को राष्ट्रीय और इंटरनेशनल बिसनेस मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने में सहायता करना है। यह योजना MSME को अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद करती है और इसमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं शामिल हैं। योजना के मुख्य उद्देश्य बाजार पहुंच में वृद्धि करना है जेसे की व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके MSME को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद करना, MSME को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आने और ऑनलाइन बिक्री करने में सहायता प्रदान करना, पैकेजिंग, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं और अन्य विपणन-संबंधी विषयों पर जागरूकता बढ़ाना है |

महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए "वुमनिया" कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया जिसमे महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और उन्हें विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में अपने उत्पाद बेचने के अवसर प्रदान करके महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। "वुमनिया" महिला MSME उद्यमियों के लिए सार्वजनिक खरीद में 3 प्रतिशत आरक्षण की सरकार की पहल के अनुरूप है और इससे खरीद की अपार संभावनाएँ है

उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP)- इस योजना के अंतर्गत युवाओं तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों में उद्योग करने का कौशल विकसित करना है। यह उद्योगों के प्रति जागरूकता, उद्यमिता-सह-कौशल विकास, और मैनेजमेंट डेवलपमेंट जैसे मॉड्यूल के माध्यम से तकनीकी, व्यवसायिक और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह पहल प्रतिभागियों को आवश्यक कौशल, मेंटरिंग और आधुनिक व्यापारिक प्रथाओं से परिचित कराती है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है और नए MSME स्थापित किए जा सकें। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) का उद्देश्य युवाओं, महिलाओं, कारीगरों और कमजोर वर्गों के बीच उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम तकनीकी, व्यावसायिक और प्रबंधकीय प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें उद्यमिता जागरूकता, कौशल विकास और प्रबंधन विकास जैसे मॉड्यूल शामिल हैं, ताकि इच्छुक और मौजूदा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके। व्यावसायिक कौशल और ज्ञान प्रदान करना, उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आत्मविश्वास और आवश्यक साधनों से लैस करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया के बारे में जानकारी प्रदान करना इस योजना के लाभ है|

सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास (एमएसई-सीडीपी) -- सूक्ष्म और लघु उद्यम समूह विकास (MSE-CDP) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य क्लस्टर दृष्टिकोण का उपयोग करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, वित्तीय सहायता के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास, जैसे सामान्य सुविधा केंद्र, औद्योगिक एस्टेट्स और 'फ्लैटेड फैक्टरी कॉम्प्लेक्स' की स्थापना या उन्नयन किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता में सुधार करना है और बाजार तक पहुंच को बढ़ाना है।उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी और कौशल विकास के लिए मदद करना इस योजना के प्रमुख लाभ है|

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) - एनएसआईसी, एक आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित भारत सरकार का उद्यम है, जो देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। यह वित्तपोषण, मार्केटिंग, कच्चे माल की आपूर्ति, प्रौद्योगिकी सहायता और निर्यात संवर्धन जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है।कच्चे माल की खरीद, मार्केटिंग गतिविधियों, बैंकों के साथ गठजोड़ के माध्यम से ऋण सुविधाएँ प्रदान करती है|

स्टार्टअप इंडिया- स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना

है। यह 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था, ताकि उद्यमियों को वित्तीय सहायता, मेंटरशिप और नियामक ढांचे में मदद मिल सके, और भारत में बेरोजगारों की जगह लोग स्वयं के उद्योग स्थापित कर नौकरी देने वालों की संख्या बढ़ सके। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन, वित्तीय सहायता एवं शिक्षा और उद्योग के बीच साझेदारी और इनक्यूबेशन को बढ़ावा देना एस योजना के प्रमुख लाभ है|

GeM (Government e-Marketplace)- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इस योजना का शुभारम्भ 9 अगस्त, 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए एक ओपन और ट्रांसपरेंट परचेसिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाने के उद्देश्य से की गई थी। GeM ने हस्तशिल्प और हथकरघा, सहायक उपकरण, जूट और कॉयर उत्पाद, बांस उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, मसाले, गृह सज्जा और कार्यालय साज-सज्जा जैसे उत्पादों को खरीद में आसानी के लिए विशेष रूप से वर्गीकृत किया है। इस योजना में सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों (वोकल फॉर लोकल)को प्राथमिकता दी जाती है। GeM सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के उद्यमियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। MSMEs से 25 प्रतिशत की अनिवार्य खरीद के लक्ष्य और SC/ST समुदायों के MSME उद्यमियों से 4 प्रतिशत वस्तुओं और सेवाओं की उप-खरीद के उप-लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य पर आधारित है।

सुझाव

1. स्थानीय उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मार्केटिंग अभियान चलाये जाने चाहिए।
2. शिक्षण संस्थानों में स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहन देना चाहिए।
3. कारीगरों और MSME को तकनीकी प्रशिक्षण देने की योजनाये बनाना चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण में कारीगरों की पहुच सरल करना चाहिए जिससे अधिक से अधिक कारीगर प्रशिक्षण ले सके|
4. स्थानीय उद्यमों के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ई-कॉमर्स सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।

निष्कर्ष- वोकल फॉर लोकल अभियान भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम है। यदि वोकल फॉर लोकल अभियान को नीति और शासन दोनों स्तरों पर निरंतर सहयोग मिलता रहे तो वोकल फॉर लोकल अभियान न केवल रोजगार निर्माण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय नवाचारों को भी

वैश्विक पहचान दिलाने में सक्षम होगा। यह अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सतत विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम साबित हो सकता है|

संदर्भ सूची

1. https://spmrf.org/vocal-for-local-will-open-the-path-of-self-reliance/
2. Revitalizing the Indian Toy Industry: PM Modi's 'Vocal for Local' Campaign and Its Impact | NFS
3. साहू, अभिलाषा,(2023),” वोकल फोर लोकल की प्रासंगिकता आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में” Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika, ISSN No. 2321-290X, Vol.- X, Issue-VII March-2023 http://www.socialresearchfoundation.com/new/publish-journal.php?editID=512
4. NITI Ayog, Annual Report, (2021-22), Unit VIII, page no. 141. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-02/Annual-Report-2021-2022-Hindi.pdf https://msme.gov.in/prime-minister-employment-generation-programme-and-other-credit-support-schemes
5. https://msme.gov.in/development-khadi-village-and-coir-industries
6. https://msme.gov.in/1-marketing-promotion-schemes
7. https://msme.gov.in/entrepreneurship-and-skill-development-programs
8. https://msme.gov.in/micro-small-enterprises-cluster-development-mse-cdp
9. https://www.startupindia.gov.in/hindi/
10. https://gem.gov.in/
11. https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2106076®=3&lang=1
12. https://assets-bg.gem.gov.in/resources/pdf/GeM_handbook.pdf